Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

जनवरी (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रेन पालिसी 3
- देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक 3
- उत्तराखंड के 1800 गाँवों में अब रेगुलर पुलिस सँभालेगी कानून-व्यवस्था 4
- मुख्यमंत्री ने जारी की नाबार्ड की फोकस रिपोर्ट 4
- चीन सीमा को जोड़ने वाले उत्तराखंड के दो पुल राष्ट्र को समर्पित 4
- मुख्यमंत्री ने की युवा महोत्सव में मंगल दलों की प्रोत्साहन राशि में एक हज़ार रुपए की वृद्धि की घोषणा 5
- मसूरी के कैंपटी में बनेगी प्रदेश की पहली टनल पार्किंग 5
- देश के शीर्ष तीन पुलिस स्टेशनों में शुमार हुआ चंपावत का बनबसा थाना 6
- उत्तराखंड में सीमांत गाँवों को आबाद करेगा बॉर्डर टूरिज्म 7
- उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. अरुण कुकसाल को मिलेगा प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 7
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विवि पाठ्यक्रम में शामिल होगा नैतिक शिक्षा संबंधी विषय 8
- रुद्रप्रयाग ज़िला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवॉर्ड 2022 के तहत मिला सिल्वर मेडल 8
- उत्तराखंड में महिलाओं को मिला क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंज़ूरी 9
- उत्तराखंड में तीन और स्थानों पर शुरू होंगी हेली सेवाएँ 10
- उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी 10
- ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट-2023 - 'गुल्लक' 11
- उत्तराखंड के सभी पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता का होगा सर्वे 11
- 'क्यू मैनेजमेंट सिस्टम 12
- उत्तराखंड में भारत सीरीज नंबर जल्द होंगे शुरू 12
- जोशीमठ आपदा प्रभावितों को बसाने के लिये चार स्थान चिह्नित 12
- चारधाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना 13
- उत्तराखंड के दो स्टार्टअप को मिला राष्ट्रीय अवॉर्ड 13
- उत्तराखंड की महिला कर्मियों के प्रसूति व बाल देखभाल अवकाश की गणना एमएसीपीएस में होगी 14
- उत्तराखंड में उत्कृष्ट सेवा के लिये 96 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान 14
- उत्तराखंड गृह विभाग में अब महिलाओं का दबदबा 15
- एक अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे प्रदेश के 5500 सरकारी वाहन 15
- गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा उत्तराखंड का छोलिया नृत्य 16
- एसएसपी दून और एसटीएफ को राज्यपाल पदक 16
- उत्तराखंड में होमगार्ड और अग्निशमन सेवा के अधिकारियों व कर्मियों को राष्ट्रपति पदक 16
- सेना मेडल से सम्मानित होंगे उत्तराखंड के मेजर प्रशांत भट्ट 17
- उत्तराखंड के खिलाड़ियों के 4% आरक्षण के अध्यादेश को मिली मंज़ूरी 17
- उत्तराखंड सरकार अगले दो साल में बनवाएगी 50 हज़ार पॉली हाउस 18
- प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लागू होगा समान शैक्षिक कैलेंडर 18
- गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झाँकी को मिला प्रथम स्थान 19

नोट :

उत्तराखंड

उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रेन पालिसी

चर्चा में क्यों ?

1 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास सचिव हरि चंद्र सेमवाल ने बताया कि प्रदेश में सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिये प्रदेश सरकार स्ट्रीट चिल्ड्रेन पालिसी लाने जा रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों के क्रम में इस नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास सचिव हरि चंद्र सेमवाल ने बताया कि अब प्रदेश स्ट्रीट चिल्ड्रेन पालिसी के संबंध में श्रम, पुलिस, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण समेत विभिन्न विभागों से राय ली जा रही है। जल्द ही नीति को अंतिम रूप देकर स्वीकृति के लिये कैबिनेट में रखा जाएगा। इस नीति में ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिये समाज का सहयोग लेने के साथ ही विभिन्न कंपनियों व संस्थाओं के सीएसआर मद से भी कदम उठाए जाएंगे।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कुछ समय पहले सभी राज्यों को स्ट्रीट चिल्ड्रेन के पुनर्वास के दृष्टिगत नीति बनाने को कहा था। इस कड़ी में उत्तराखंड में भी इसकी शुरूआत की गई।

विदित है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे बच्चों की संख्या न के बराबर है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, नैनीताल, कोटद्वार जैसे शहरी क्षेत्रों में अधिक है। बालश्रम, भिक्षावृत्ति, निराश्रित, बेसहारा व कूड़ा बीनने वाले बच्चों को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया।

इसके बाद ऐसे बच्चों के पुनर्वास के दृष्टिगत स्ट्रीट चिल्ड्रेन नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट में ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये शिक्षा, कौशल विकास, खाद्य, स्वास्थ्य, पुनर्वास, रोज़गार, सुरक्षा जैसे विषयों के दृष्टिगत विभागों के आपसी समन्वय से प्रभावी कदम उठाने पर ज़ोर दिया गया है।

हरि चंद्र सेमवाल ने बताया कि अब इस बारे में संबंधित विभागों से राय ली जा रही है। समाज के विभिन्न वर्गों, गैर सरकारी संस्थाओं से भी सुझाव लिये जा रहे हैं। हितधारकों से राय प्राप्त करने के बाद स्ट्रीट चिल्ड्रेन पालिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा।

देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक

चर्चा में क्यों ?

2 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना उत्तराखंड के देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र जसवंत सिंह ग्राउंड (महिंद्रा ग्राउंड) में देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है, जिसका उद्घाटन 14 जनवरी को देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

प्रमुख बिंदु

उत्तराखंड सब एरिया से मिली जानकारी के अनुसार इस ट्रैक के निर्माण में सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट मैटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। रनिंग ट्रैक का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

रनिंग ट्रैक को आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है ताकि सभी आयु के लोग आसानी से गर्मी, सर्दी और बरसात में इसका इस्तेमाल कर सकें। इसका सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को होगा। बरसात में अक्सर बारिश के चलते वे अभ्यास नहीं कर पाते। अब इस ट्रैक पर वे रोजाना अभ्यास कर सकेंगे।

देहरादून के जसवंत सिंह ग्राउंड में मैराथन के साथ ही अन्य आयोजन भी होंगे। ट्रैक के किनारे डिस्प्ले लगाने की योजना है ताकि दौड़ते समय पता चल सके कि कितनी दौड़ लगा ली है। डिस्पले के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाएगा ताकि वे अच्छी दौड़ कर सकें। ग्राउंड में चारों तरफ से सोलर लाइट लगाने की भी योजना है।

रनिंग ट्रैक के अलावा रक्षामंत्री राज्य के पहले वार मेमोरियल का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण कैंट क्षेत्र चीड़बाग में हो रहा है।

नोट :

उत्तराखंड के 1800 गाँवों में अब रेगुलर पुलिस सँभालेगी कानून-व्यवस्था

चर्चा में क्यों ?

2 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के अपर गृह सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि राज्य के 1800 राजस्व गाँवों में कानून व्यवस्था अब रेगुलर पुलिस सँभालेगी। राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर इन गाँवों को रेगुलर पुलिस के अधीन करने के लिये अधिसूचित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

अपर गृह सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 7500 गाँव ऐसे हैं, जहाँ पर कानून-व्यवस्था का जिम्मा राजस्व पुलिस के पास है। लेकिन अब वर्षों पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर सरकार इन गाँवों को रेगुलर पुलिस के अधीन लाने जा रही है। इन गाँवों में नियमित पुलिस व्यवस्था होने से अपराध व असामाजिक गतिविधियों में कमी आएगी।

राज्य में रेगुलर पुलिस की कानून-व्यवस्था के अंतर्गत पहले चरण में 52 थाने और 19 पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार किया जाएगा।

दूसरे चरण में 6 नए थाने व 20 पुलिस चौकियों का गठन किया जाएगा। इसके तहत नए थाने व चौकियों का गठन कर लगभग 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन करने की प्रकिया जल्द पूरी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से नियमित पुलिस व्यवस्था के लिये अधिसूचित राजस्व गाँवों में देहरादून ज़िले के 4, उत्तरकाशी के 182, चमोली के 262, टिहरी के 157, पौड़ी के 148, रुद्रप्रयाग के 63, नैनीताल के 39, अल्मोड़ा के 231, पिथौरागढ़ के 595, बागेश्वर के 106 एवं चंपावत के 13 गाँव शामिल हैं।

ज्ञातव्य है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में राजस्व पुलिस पर उठे सवालों के बाद सरकार ने इसे रेगुलर पुलिस के अधीन करने का बड़ा निर्णय लिया है।

दरअसल, उत्तराखंड को तीन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। इन तीनों में अलग-अलग अधिनियम लागू होते हैं, जो राजस्व अधिकारियों को गिरफ्तारी और जाँच का अधिकार देते हैं। पहला क्षेत्र है कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन की पहाड़ी पट्टी। दूसरा, टिहरी और उत्तरकाशी ज़िले की पहाड़ी पट्टी और तीसरा क्षेत्र है देहरादून ज़िले का जौनसार-बावर क्षेत्र।

मुख्यमंत्री ने जारी की नाबार्ड की फोकस रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

3 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की फोकस रिपोर्ट जारी की, जिसके अंतर्गत राज्य में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर,एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये नाबार्ड 30301 करोड़ रुपए का लोन देगा।

प्रमुख बिंदु

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 की शुरुआत करते हुए यह रिपोर्ट जारी की है।

नए वित्तीय वर्ष में नाबार्ड, राज्य को 30301 करोड़ रुपए का ऋण देगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष नाबार्ड ने प्रदेश को दस हज़ार करोड़ रुपए की 4515 परियोजनाओं की मंजूरी दी थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैंकों को इन योजनाओं में बेहतर काम करने, सभी की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिये। यह किसानों, बागवानी तथा छोटे-छोटे उद्योगों में लगे लोगों की आजीविका बढ़ाने में कारगर साबित होगी।

उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी ऋण की कमी वाले तीन ज़िलों में ऋण आवंटन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

चीन सीमा को जोड़ने वाले उत्तराखंड के दो पुल राष्ट्र को समर्पित

चर्चा में क्यों ?

3 जनवरी, 2023 को देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीन सीमा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर नवनिर्मित उत्तराखंड के दो पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इन पुलों का निर्माण टनकपुर-तवाघाट-लिपुलेख सड़क पर सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

राज्य में टनकपुर-तवाघाट-लिपुलेख सड़क पर एक पुल धौलीगंगा में है। धौलीगंगा और काली गंगा के संगम स्थल पर बनाए गए इस सुपर स्ट्रक्चर पुल की लंबाई 80 मीटर है।

दूसरा पुल इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जौलजीबी के पास किमखोला के गुमरोड़ी में बनाया गया है। इस पुल की लंबाई 35 मीटर है।

ज्ञातव्य है कि इन पुलों का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 27 दिसंबर को किया जाना था लेकिन उस दिन पुलों का उद्घाटन किन्हीं कारणोवश नहीं हो सका।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के ओसी रमेश गणपति ने बताया कि दोनों पुलों का निर्माण प्रोजेक्ट हीरक के तहत 1447 बीसीसी/47बीआरटीएफ ने किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में मज़बूत पुलों के बनने से वाहनों की आवाजाही और अधिक सुगम हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने की युवा महोत्सव में मंगल दलों की प्रोत्साहन राशि में एक हज़ार रुपए की वृद्धि की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

4 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रदेश के युवक व महिला मंगल दलों की प्रोत्साहन राशि में एक हज़ार रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राज्य एवं जनपद स्तर पर युवा दिवस मनाया जाएगा। ऐसे महोत्सव हमारी संस्कृति एवं परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं।

उन्होंने बताया कि इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में चयनित प्रतिभागी 12 जनवरी को धारवाड़ कर्नाटक में राष्ट्रीय स्तर के युवा महोत्सव में हिस्सा लेंगे। साथ ही उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर के रूप में यहाँ की संस्कृति को पूरे देश के सामने रखेंगे।

इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में लोक गीत, लोक नृत्य और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े कई कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाएंगे।

राज्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निदेशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि प्रोत्साहन राशि बढ़ने का लाभ करीब सात हज़ार मंगल दलों के सदस्यों को लाभ मिलेगा। अब इन दलों को चार की जगह पाँच हज़ार रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 2021-22 में उत्कृष्ट कार्यों के लिये युवक एवं महिला मंगल दलों को राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवॉर्ड से सम्मानित किया। युवक मंगल दल मनकटिया विकासखंड मूनाकोट पिथौरागढ़ को प्रथम, युवक मंगल दल धुरा नंदानगर विकासखंड घाट चमोली को द्वितीय और युवक मंगल दल खेड़ाजट विकासखंड नारसन हरिद्वार को तृतीय पुरस्कार मिला।

इसके अलावा महिला मंगल दल नंदानगर विकासखंड घाट चमोली को प्रथम, महिला मंगल दल किसमिला विकासखंड कपकोट बागेश्वर को द्वितीय और महिला मंगल दल बड़ोवाला विकासखंड डोईवाला व महिला मंगल दल हसनपुर विकासखंड भगवानपुर को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार मिला।

इसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दलों को क्रमश: एक लाख, 50 हज़ार और 25 हज़ार रुपए की धनराशि दी गई।

ज्ञातव्य है कि मंगल दल समाज के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ये सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुँचाते हैं और लोगों को इनका लाभ लेने के लिये प्रेरित करते हैं। इसके अलावा ये दल शिक्षा एवं स्वरोज़गार के लिये भी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही, हमारी संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखने में भी उत्कृष्ट भूमिका निभाते हैं।

मसूरी के कैंपटी में बनेगी प्रदेश की पहली टनल पार्किंग

चर्चा में क्यों ?

4 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने देहरादून में टनल पार्किंग, ऑटोमेटेड पार्किंग को लेकर सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में बताया कि मसूरी के कैंपटी क्षेत्र में प्रदेश की पहली टनल पार्किंग बनेगी। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को शासन ने मंजूरी दे दी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बताया कि यह पार्किंग नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएचआईडीसीएल) तैयार करेगा। इसके अलावा हरिद्वार में भी हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) और एनएचआईडीसीएल के संयुक्त तत्वावधान में पाँच ऑटोमेटेड पार्किंग को मंजूरी दी गई। इनकी डीपीआर जल्द तैयार की जाएगी।

इसके अलावा प्रदेश में दस बड़े पार्किंग प्रोजेक्ट की डीपीआर अंतिम चरण में है।

प्रदेश में 158 नई पार्किंग का रोडमैप तैयार किया गया है। इनमें 10,000 से ज्यादा वाहन पार्क हो सकेंगे। इनमें 50 भूतल पार्किंग, 88 मल्टी लेवल कार पार्किंग, नौ ऑटोमेटेड और 12 टनल पार्किंग शामिल हैं।

ज़िले एवं नई पार्किंग-

ज़िला	श्रेणी-ए	श्रेणी-बी
अल्मोड़ा	17	05
बागेश्वर	06	02
चमोली	11	05
चंपावत	06	01
देहरादून	03	01
हरिद्वार	05	00
नैनीताल	06	06
पौड़ी	10	07
पिथौरागढ़	10	06
रुद्रप्रयाग	04	04
टिहरी	18	07
उत्तरकाशी	10	06
ऊधमसिंह नगर	02	00

देश के शीर्ष तीन पुलिस स्टेशनों में शुमार हुआ चंपावत का बनबसा थाना

चर्चा में क्यों ?

5 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेपाल सीमा से लगे उत्तराखंड के चंपावत ज़िले का बनबसा थाना देश के शीर्ष तीन थानों में शुमार हो गया है।

प्रमुख बिंदु

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस के लिये यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चंपावत ज़िले के बनबसा थाना का चयन देश के करीब 16 हज़ार पुलिस स्टेशनों में से हुआ है। वर्तमान में राज्य में 160 पुलिस स्टेशन संचालित हो रहे हैं।

विदित है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से विधायक भी हैं।

पुलिस विभाग के सूत्रों के मुताबिक, बनबसा पुलिस स्टेशन को बेहतर कानून-व्यवस्था, मुकदमों के त्वरित निपटारे, कंप्यूटराइजेशन व अन्य मानकों में अच्छे प्रदर्शन की वजह से श्रेष्ठतम की सूची में शामिल किया गया है।

ज्ञातव्य है कि 20 जनवरी को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस स्टेशन के एसएचओ लक्ष्मण सिंह जगवाण को यह पुरस्कार देंगे। प्रथम तीन में कौन-सी रैंकिंग मिलेगी, इसकी घोषणा उसी दिन होगी।

राज्य के चंपावत ज़िले के एसपी देवेंद्र पींचा ने पुरस्कार की पुष्टि की है। वर्ष 2022 में भी बनबसा थाने को देशभर में सातवीं रैंक मिली थी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अपराध नियंत्रण और आम नागरिकों के साथ व्यवहार आदि मानकों पर शीर्ष थानों का निर्धारण करता है।

नोट :

एसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि बनबसा से नेपाल के लिये वैध आवाजाही होती है। रोजाना औसतन तीन हजार से अधिक देसी-विदेशी लोगों की आवाजाही होती है। बनबसा सीमा से होने वाली मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये तीन दशक पहले बने इस थाने और बनबसा शारदा बैराज पुलिस चौकी की शानदार भूमिका रही है।

उत्तराखंड में सीमांत गाँवों को आबाद करेगा बॉर्डर टूरिज्म

चर्चा में क्यों ?

5 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस नेगी ने बताया कि राज्य के सीमांत गाँवों को आबाद करने के लिये उत्तराखंड सरकार 'बॉर्डर टूरिज्म' योजना शुरू करने की पहल करने जा रही है।

प्रमुख बिंदु

इसके लिये राज्य की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय में योजना का विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग को योजना का खाका तैयार करने के निर्देश दिये हैं।

डॉ. एस.एस नेगी ने बताया कि राज्य के सीमांत गाँवों को आबाद करने के लिये राज्य सरकार ने बॉर्डर टूरिज्म के लिये उत्तराखंड के चार ब्लाक उत्तरकाशी में भटवाड़ी, चमोली में जोशीमठ और पिथौरागढ़ में मुनस्यारी व धारचूला का चयन किया है। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

विदित है कि अभी तक पर्यटकों को सीमांत क्षेत्रों में जाने के लिये ज़िलाधिकारी की ओर से इनर लाइन परमिट दिया जाता है। उत्तरकाशी ज़िले की गंगा घाटी के दो गाँव नेलांग और जादूंग 60 साल से वीरान हैं। यहीं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा भी पड़ता है। इस क्षेत्र में जाने के लिये वन विभाग से अलग से अनुमति लेनी पड़ती है। इस बात की संभावना तलाशी जा रही है कि कैसे अनुमति की इस प्रक्रिया को और सरल किया जाए।

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, अधिकतर सीमांत गाँव छह माह बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ होने वाले कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ होम स्टे तैयार किये जाएंगे। नए पर्यटन स्थलों का चिन्हीकरण किया जाएगा। पर्यटन से जुड़े हर काम में स्थानीय लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

डॉ. एस.एस नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बार्डर टूरिज्म को बढ़ावा के लिये रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सरकार चाहती है कि सीमावर्ती गाँवों में फिर से रौनक लौटे, लेकिन इससे पहले वहाँ लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये संसाधन जुटाने होंगे। बार्डर टूरिज्म इस दिशा में कारगर नीति हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि भारत-चीन के बीच उत्तराखंड में 345 किमी. लंबी सीमा है। वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कई गाँवों को खाली करा दिया गया था। इनमें से कई गाँव आज भी निर्जन हैं। देश की सीमा से लगे ये गाँव किसी प्रहरी की भाँति काम करते थे।

सैन्य मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा के करीब बसावट सुरक्षा के लिहाज से महत्त्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में बार्डर टूरिज़्म की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक वहाँ लोगों को बसाना संभव नहीं हो पाता, तब तक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. अरुण कुकसाल को मिलेगा प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

6 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. अरुण कुकसाल को उनकी चर्चित पुस्तक 'चले साथ पहाड़' के लिये 'पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित 'राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार, 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

पौड़ी गढ़वाल के चामी गाँव में डॉ. अरुण कुकसाल का जन्म 8 अक्टूबर 1959 को हुआ था। वर्तमान में वे श्रीकोट-श्रीनगर में रहते हैं। डॉ. अरुण कुकसाल पौड़ी के मनरेगा विभाग में लोकपाल पद पर कार्य कर रहे हैं। अरुण कुकसाल ने अब तक सात पुस्तकों की रचना की है।

नोट :

डॉ. अरुण कुकसाल हिमालयी समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक मुद्दों पर प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं तथा सोशल मीडिया में नियमित लेखन से जुड़े हैं। इनकी उद्यमिता विकास, यात्रा साहित्य तथा सामाजिक-सांस्कृतिक विषयक 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

गौरतलब है की पूर्व में डॉ. अरुण कुकसाल को उद्यमिता शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये 'राष्ट्रीय उद्यमी उत्प्रेरणा प्रशिक्षक सम्मान' प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में डॉ. अरुण कुकसाल अपने पैतृक गाँव चामी में बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिये पुस्तकालय संचालन, कंप्यूटर प्रशिक्षण और कैरियर मार्गदर्शन के कार्य में सक्रिय हैं। साथ ही, लोकपाल (मनरेगा), पौड़ी (गढ़वाल) के पद पर अपनी विशेषज्ञ सेवाएँ प्रदान कर रहें हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विवि पाठ्यक्रम में शामिल होगा नैतिक शिक्षा संबंधी विषय

चर्चा में क्यों ?

8 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून के सभागार में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विवि से संबद्ध अशासकीय व निजी शिक्षण संस्थानों के साथ हुई बैठक में बताया कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता व छात्र-छात्राओं में नैतिक मूल्यों के विकास के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत विवि पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा संबंधी विषय शामिल किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिये सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम और एक चुनाव कार्य योजना को लागू किया जाएगा।

राज्य के सभी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की डिजिटल हेल्थ आईडी अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी। इससे छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियाँ ऑनलाइन सुरक्षित रह सकेंगी और ज़रूरत पड़ने पर उपयोग कर सकेंगे।

इसके अलावा सभी छात्र-छात्राओं के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे, जिसके लिये राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण विवि के साथ क्यूआर कोड साझा करेगा।

डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को स्वैच्छिक रक्तदान के लिये ई-रक्तकोश, आरोग्य सेतु एप, विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, जिससे ज़रूरत पड़ने पर रक्तदान के लिये बुलाया जा सके।

बैठक में श्रीदेव सुमन विवि के कुलपति प्रो. महावीर सिंह रावत ने बताया कि राज्य के संस्थानों में नशा मुक्त अभियान, तंबाकू मुक्त अभियान संचालित किया जाएगा। सभी निजी शिक्षण संस्थानों से नेक मूल्यांकन के लिये अनिवार्य रूप से आवेदन करने को कहा। इसके लिये विवि के माध्यम से नेक मूल्यांकन कार्यशाला का आयोजन फरवरी में कराया जाएगा।

रुद्रप्रयाग ज़िला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवॉर्ड 2022 के तहत मिला सिल्वर मेडल

चर्चा में क्यों ?

7 जनवरी, 2023 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िला प्रशासन को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के सातवें संस्करण में सिल्वर मेडल प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रुद्रप्रयाग के ज़िलाधिकारी मयूर दीक्षित और उपज़िलाधिकारी ऊखीमठ जितेंद्र वर्मा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। रुद्रप्रयाग ज़िला प्रशासन को यह पुरस्कार डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम (डीआरएस) कैटिगरी में दिया गया है।

ज़िलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में ज़िला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक समेत अन्य प्लास्टिक के सामान का निस्तारण करने के लिये रिसाइक्लिंग की अनोखी व्यवस्था की थी।

इसके लिये रिसाइक्लिंग संस्था के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केदारनाथ यात्रा मार्ग, चोपता, तुंगनाथ और देवरियाताल मार्ग पर क्यूआर कोड की व्यवस्था लागू की गई थी। प्लास्टिक सामान के निस्तारण के लिये क्यूआर कोड सिस्टम शुरू किया गया था जिसके तहत प्लास्टिक बोतलों की टैगिंग की गई थी। हर क्यूआर कोड लगी बोतल पर बिक्री के समय 10 रुपए अतिरिक्त वसूले जाते हैं, वहीं प्रत्येक बोतल वापस जमा करने वाले को 10 रुपए दिये जाते हैं।

नोट :

ज़िलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि वर्ष 2022 में पानी की बोतलों पर क्यूआर कोड लगाने के साथ प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी जबकि कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर भी इसे लागू किया गया।

डिजिटल इंडिया अवार्ड्स (DIA) डिजिटल पहलों को सामने लाने का अवसर प्रदान करता है। ये पुरस्कार सभी स्तरों पर सरकारी संस्थाओं द्वारा नवीन डिजिटल समाधानों को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिये भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तत्त्वावधान में स्थापित किये गए हैं।

डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं बल्कि स्टार्टअप्स को भी डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिये प्रेरित करना है।

डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के इस संस्करण में सात श्रेणियों में 22 टीमों को पुरस्कार प्रदान किये गए।

उत्तराखंड में महिलाओं को मिला क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

10 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) ने उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 को मंज़ूरी दे दी। राजभवन से विधेयक को विधायी विभाग भेज दिया गया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

राजभवन को 14 विधेयक मंज़ूरी के लिये भेजे गए थे। इनमें से महिला आरक्षण समेत 12 को मंज़ूरी मिल गई है, जबकि भारतीय स्टांप उत्तराखंड संशोधन विधेयक और हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक को राजभवन से अभी मंज़ूरी नहीं मिली है।

राज्यपाल की मंज़ूरी के साथ ही उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा, जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास (डोमिसाइल) है। बेशक वे राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर निवास कर रही हों।

प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर, 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में 14 विधेयक पारित हुए थे। अधिकतर संशोधित विधेयक थे, इनमें महिला आरक्षण बिल भी शामिल था।

दरअसल, राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंज़ूरी मिल गई थी, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन रहा। राजभवन ने विधेयक को मंज़ूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इससे विधेयक को मंज़ूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया।

हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित प्रवर सेवा के पदों के लिये आयोजित परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों के 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। हरियाणा की पवित्रा चौहान व अन्य अभ्यर्थियों ने यह याचिका दायर की थी।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार की विशेष अनुग्रह याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस तरह आरक्षण बरकरार रहा। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में सात फरवरी को सुनवाई होनी है।

महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर कब क्या हुआ-

18 जुलाई, 2001 को अंतरिम सरकार ने 20 प्रतिशत आरक्षण का शासनादेश जारी किया।

24 जुलाई, 2006 को तत्कालीन तिवारी सरकार ने आरक्षण को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया।

26 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगाई।

04 नवंबर, 2022 को सरकार की एसएलपी पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

29 नवंबर, 2022 को सरकार ने विधानसभा के सदन में विधेयक पेश किया।

30 नवंबर, 2022 को सरकार ने विधेयक को सर्वसंमति से पारित कराकर राजभवन भेजा।

10 जनवरी, 2022 को राज्यपाल ने विधेयक को मंज़ूरी दे दी।

नोट :

उत्तराखंड में तीन और स्थानों पर शुरू होंगी हेली सेवाएँ

चर्चा में क्यों ?

12 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि प्रदेश में हेली सेवाओं का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाने के क्रम में अब प्रदेश सरकार ने तीन और स्थानों के लिये हेली सेवाएँ चलाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि प्रदेश में हेली सेवाओं का दायरा बढ़ाने के अंतर्गत अब देहरादून को नैनीताल व जोशीमठ और हल्द्वानी को मुनस्यारी से जोड़ने की तैयारी है।

इसमें से दो हेली सेवाएँ देहरादून से संचालित होंगी, जिसमें देहरादून से नैनीताल और देहरादून से जोशीमठ हेली सेवा शामिल है। इसके अलावा हल्द्वानी से मुनस्यारी को भी हेली सेवा के लिये उपयुक्त पाते हुए यहाँ भी हेली सेवा शुरू करने की तैयारी है।

उन्होंने बताया कि पर्यटन एवं तीर्थाटन के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण देवभूमि की वादियों की हवाई सैर अब आसान और सुलभ हो रही है। सैलानियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार हेली सेवाओं को लगातार विस्तार दे रही है। इस क्रम में प्रदेश में नए हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं।

सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि प्रदेश में हेली सेवाओं को विस्तार देने में केंद्र सरकार की 'उड़ान योजना'की अहम भूमिका है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी देहरादून से चिन्यालीसौड़, देहरादून से गौचर, देहरादून से टिहरी, देहरादून से श्रीनगर, देहरादून से अल्मोड़ा तथा हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिये हेली सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

विदित है कि तीर्थाटन हेतु देहरादून से केदारनाथ व चमोली ज़िले के विभिन्न स्थानों से केदारनाथ व हेमकुंड साहिब के लिये हेली सेवाएँ संचालित की जा रही हैं।

उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों ?

12 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई। जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में महिलाओं के लिये सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

गौरतलब है कि 10 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) ने उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 को मंज़ूरी दी थी, जिसके बाद यह विधेयक अधिनियम बना।

उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2022 बनने के बाद राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस अधिसूचना में अधिनियम के पालन के लिये उत्तरदायित्व एवं शक्ति, प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति एवं कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के बारे में बताया गया है।

अधिसूचना में कहा गया कि प्रदेश की विषम भौगोलिक संरचना की वजह से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग विकट जीवन यापन करते हैं। खासतौर पर राज्य की महिलाएँ विषम परिस्थितियों में जीवन का निर्वाह करती हैं। इस वजह से इन महिलाओं का जीवन स्तर अन्य राज्यों की महिलाओं से निम्न है।

राज्य की महिलाएँ अपेक्षित, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर को नहीं पा सकी हैं तथा राज्य में सरकारी सेवाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी काफी कम है। सामाजिक न्याय, समानता, जीवन स्तर में सुधार, लोक नियोजन में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिये राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया।

नोट :

ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट-2023 - 'गुल्लक'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता समिट-2023 'गुल्लक'का शुभारंभ किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

प्रमुख बिंदु

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ग्रामीण उद्यमियों हेतु आयोजित 'गुल्लक' नामक यह कार्यक्रम, देशभर में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें निवेशक ग्रामीण उद्यमियों के साथ सीधे संवाद कर उनके उद्यमों में निवेश कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास को गति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा विगत वर्ष 'रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर्स'की स्थापना जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में और जनपद पौड़ी के कोटद्वार में की गई। वर्तमान में इन 'रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर्स' के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

इनक्यूबेटर्स के अच्छे परिणामों को देखते हुए इस योजना को हब एवं स्पॉक मॉडल के अंतर्गत राज्य के अन्य 11 जनपदों में क्रियाशील किये जाने हेतु 'रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर' के स्पॉक स्थापित किये जाएंगे। इन इनक्यूबेटर्स के माध्यम से उद्यमियों को नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण उद्यमिता के विकास से राज्य के युवा स्वरोज़गार से जुड़ेंगे तथा नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे। ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादों के विपणन की बेहतर व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की समस्या से निजात पाने के लिये विशेष रूप से कार्य कर रही है। राज्य के नागरिकों को अपने स्थान पर रहकर ही स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा राज्य के सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की केंद्र पोषित, राज्य पोषित और वाह्य सहायतित स्वरोज़गार-परक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले व्यवसाय में महिलाओं की सहभागिता अधिक रहती है, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये विशेष रूप से प्रयास कर रही है तथा 25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने की योजना बनाई है, उन्हें भी उद्यमिता से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशन में आगामी एक माह तक 'मिशन अंत्योदय सर्वे' मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इस सर्वे में सामुदायिक काडर की महिलाओं द्वारा आर्थिक विकास, गाँवों की आधारभूत संरचना, सेवाओं और सामाजिक न्याय से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

उत्तराखंड के सभी पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता का होगा सर्वे

चर्चा में क्यों ?

14 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने जोशीमठ आपदा से सबक लेते हुए प्रदेश के सभी पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) का वैज्ञानिक व तकनीकी सर्वे कराने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु

उल्लेखनीय है कि आबादी और बेतरतीब ढंग से हो रहे निर्माण कार्यों से पर्वतीय शहरों में धारण क्षमता से अधिक दबाव बढ़ रहा है। जोशीमठ भू धंसाव के पीछे एक वजह शहर की भार वहन क्षमता से अधिक निर्माण को भी ठहराया जा रहा है।

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में तय हुआ कि पर्वतीय क्षेत्रों के सभी शहरों की धारण क्षमता का सर्वे कराने का दायित्व आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपा गया है। इसके लिये शहरी विकास, पंचायती राज समेत अन्य विभाग का सहयोग लिया जाएगा। सर्वे के लिये तकनीकी एजेंसियों का चयन किया जाएगा।

राज्य के प्रमुख पर्वतीय शहरों में मसूरी, नैनीताल, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, उत्तरकाशी, ऊखीमठ, नई टिहरी, गुप्तकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रानीखेत पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। पहले चरण में राज्य सरकार इन पर्वतीय शहरों का सर्वे करा सकती है।

इसके अंतर्गत पहले चरण में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में सर्वे कराने की मंजूरी भी दे दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जिन शहरों की भार वहन क्षमता अधिक पाई जाएगी, उनमें निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। जोशीमठ आपदा निश्चित तौर पर भविष्य के लिये सचेत कर रही है।

नोट :

'क्यू मैनेजमेंट सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

14 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि चार धामों में दर्शन के लिये जाने वाले श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में खड़े होने से छुटकारा दिलाने के लिये राज्य सरकार पहली बार 'क्यू मैनेजमेंट सिस्टम' तैयार कर रही है।

प्रमुख बिंदु

पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि चार धामों में दर्शन के लिये 'क्यू मैनेजमेंट सिस्टम' बनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा।

इसके अलावा श्रद्धालुओं को धाम में पहुँचने पर एक टोकन नंबर दिया जाएगा, जिसमें दर्शन के लिये समय निर्धारित होगा। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं को कई घंटों तक लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।

विदित है कि गत वर्ष बदरीनाथ, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होने के साथ ही पर्यटन विभाग चारधाम यात्रा के लिये पंजीकरण शुरू कर देगा। इसके लिये विभाग ने पंजीकरण की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। चार धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ न बढ़े इसलिये इस बार दो माह पहले से पंजीकरण शुरू किया जा रहा है।

उत्तराखंड में भारत सीरीज नंबर जल्द होंगे शुरू

चर्चा में क्यों ?

16 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकि ने बताया कि राज्य में परिवहन विभाग जल्द ही वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिये भारत सीरीज नंबर शुरू करने जा रहा है, जिससे एक से अधिक राज्यों में ट्रांसफर होते रहने वाले सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कार्मिकों को राहत मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

मुख्यालय सूत्रों के अनुसार परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकि के निर्देश पर परिवहन आयुक्त मुख्यालय कैबिनेट के लिये वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिये भारत सीरीज नंबर का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। बीएस सीरीज का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है।

विदित है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अगस्त 2021 में इस योजना को लॉन्च किया था।

उत्तराखंड में टैक्स राशि सामान्य वाहनों से ज्यादा होने की वजह से परिवहन विभाग इस पर पिछले काफी समय से विचार कर रहा था।

परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकि ने बताया कि दूसरे राज्य में तबादला होने पर कार्मिकों को अपने वाहन का नए सिरे से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। लंबे विचारमंथन के बाद परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय किया है।

भारत सीरीज की नंबर प्लेट लेने के लिये सेना, अर्द्धसैन्य बलों में कार्यरत कार्मिक इसके लिये पात्र होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के वे कर्मचारी भी इस सीरीज में नंबर ले सकते हैं, जिनका दूसरे राज्यों में तबादला होता रहता है। इसी प्रकार जिन प्राइवेट कंपनियों में कार्मिकों के तबादले एक से दूसरे राज्यों में होते रहते हैं, वो भी इस सीरीज के लिये आवेदन कर सकते हैं।

जोशीमठ आपदा प्रभावितों को बसाने के लिये चार स्थान चिह्नित

चर्चा में क्यों ?

17 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों को पुनर्वासित करने के लिये चार स्थानों पर भूमि का चयन कर लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ में लोगों को अच्छे घर बनाकर दिये जाने के प्रति विश्वास दिलाने के लिये पहले कोटी फार्म में स्थित उद्यान विभाग की भूमि पर तीन डेमोस्ट्रेशन भवन बनाए जाएंगे। इसमें वन, टू और थ्री बीएचके के प्री-फेब्रीकेटिड मॉडल भवन बनेंगे।

नोट :

किसको कितने कमरों का घर दिया जाएगा, यह बाद में तय किया जाएग। हालाँकि इसके लिये लोगों की भवनों की नापझोख पहले ही कर ली गई है। इसके लिये सीबीआरआई रुड़की को 21 जनवरी तक मॉडल भवन बनाने को कहा गया है।

उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावितों को बसाने के लिये पाँच स्थानों पर भूमि का चयन किया गया था। इनमें से जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर चार स्थानों को उपयुक्त पाया गया है। इनमें कोटी फार्म, एचआरडीआई की भूमि, पीपलकोटी और ढाक गांव में भूमि शामिल है।

डॉ. रंजीत सिन्हा ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की ओर से लोगों से बात की जाएगी, यदि उन्हें यह भवन पसंद आते हैं तो उनके लिये और भवन बनाए जाएंगे। सीबीआरआई की ओर से निर्माण एजेंसियाँ पहले से तय हैं, उनकी दरें भी तय हैं। सीबीआरआई की ओर से इसके लिये 400 रुपए वर्गफुट रेट तय है। इन भवनों की लाइफ 25 से 30 साल होती है।

चिह्नित चार स्थान ये हैं-

कोटी फार्म: जोशीमठ से लगभग 12 किमी दूर कोटी फार्म के लिये औली से सड़क कटती है। यहाँ राजस्व की भूमि उपलब्ध है।

ढाक गांव: मलारी रोड पर स्थित ढाक गांव जोशीमठ से करीब 12 किमी की दूरी पर स्थित है। यहाँ राजस्व की भूमि उपलब्ध है।

पीपलकोटी: जोशीमठ से करीब 36 किमी दूर पीपलकोटी में भी सरकारी ज़मीन उलब्ध है।

एचआरडीआई की भूमि: जोशीमठ से करीब नौ किमी दूर जड़ी-बूटी शोध संस्थान (एचआरडीआई) की भूमि है।

चारधाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना

चर्चा में क्यों ?

17 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि आगामी चारधाम यात्रा तक गंगोत्री व यमुनोत्री हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिये यात्रा मार्ग पर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना में सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि इस योजना के तहत प्रति 30 किमी. की दूरी पर एक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर लगभग 100 से अधिक स्टेशन स्थापित किये जाने हैं।

चारधाम में से दो धाम गंगोत्री व यमुनोत्री वाले उत्तरकाशी जनपद में योजना के तहत करीब 34 स्टेशन स्थापित किये जाएंगे। इनमें चिन्यालीसौड़, धरासू, ब्रह्मखाल, बड़कोट, यमुनोत्री, स्यानाचट्टी, जानकीचट्टी, धौंतरी व उत्तरकाशी शहर आदि में जगहें चिह्नित कर ली गई हैं।

परियोजना से जुड़ी प्रोजेक्ट मैनेजर मून बनर्जी ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर करीब 62 जगहें चिह्नित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर लगने वाले चार्जिंग स्टेशन पर एक बार में तीन इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किये जा सकेंगे। इनमें दो फास्ट और एक स्लो चार्जर होगा। न्यूनतम दरों पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सरकार की ओर से दरें निर्धारित की जाएंगी।

उत्तरकाशी के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मुकेश सैनी ने बताया कि राज्य सरकार की यह एक महत्त्वपूर्ण योजना है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से ई-वाहन मालिक व चालकों को मदद मिलेगी। साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।

सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि आपदा से जोशीमठ क्षेत्र में काम प्रभावित हो सकता है, लेकिन अन्य जगहों पर लक्ष्य अनुरूप तय समय पर चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

उत्तराखंड के दो स्टार्टअप को मिला राष्ट्रीय अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

16 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उत्तराखंड के दो स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिंगतरा एयरो स्पेस और इंडीजीनियस इनर्जी स्टार्टअप कंपनी को उत्कृष्ट कार्य करने के लिये राष्ट्रीय स्टार्टअप अवॉर्ड प्रदान किया है।

नोट :

विदित है कि वर्ष 2018 में राहुल रावत और अनिरूद्ध शर्मा ने अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के आइडिया पर स्टार्टअप बनाने का फैसला लिया। अपने आइडिया को कारोबार में बदलने के लिये दिगंतरा एयरो स्पेस स्टार्टअप कंपनी बनाई।

पिछले वर्ष जून 2022 में दिगंतरा एयरो स्पेस ने अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के लिये इसरो के सहयोग से एक उपग्रह लॉन्च किया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष में रेडिएशन में होने वाले बदलाव की जानकारी देगा।

दिगंतरा एयरो स्पेस कंपनी के सह संस्थापक व मुख्य परिचालन अधिकारी राहुल रावत ने बताया कि जिस तरह धरती पर मौसम बदलाव की जानकारी मिल रही है, उसी तरह अंतरिक्ष में रेडिएशन के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। एक ऐसा सैटेलाइट तैयार किया गया है, जिससे अंतरिक्ष में होने वाले मौसम बदलाव की सही जानकारी मिल सकती है।

इलेक्ट्रिक इनर्जी के प्रो. योगेश शर्मा ने बताया कि इंडीजीनियस इनर्जी स्टार्टअप इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने का काम कर रही है। आने वाले समय में विद्युत चलित वाहनों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इंडीजीनियस इनर्जी ने बैटरी की स्टोरेज बढ़ाने की तकनीक विकसित की है।

उत्तराखंड की महिला कर्मियों के प्रसूति व बाल देखभाल अवकाश की गणना एमएसीपीएस में होगी

चर्चा में क्यों ?

18 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों से संबंधित उनके प्रसूति अवकाश और बाल देखभाल अवकाश की गणना सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) में होगी।

प्रमुख बिंदु

उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) राधा रतूड़ी ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन को पत्र लिखकर एमएसीपी की व्यवस्था में महिला कर्मचारियों के प्रसूति अवकाश और बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि को शामिल करने का अनुरोध किया था।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि कई विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के ऐसे मामले संज्ञान में आए, उन्हें एसीपी का लाभ नहीं मिल पाया।

उन्होंने बताया कि एमएसीपी दिये जाने के लिये पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का न्यूनतम मानक उत्तम है। लेकिन इसमें बाह्य सेवा अवधि व बाह्य प्रतीक्षा अवधि तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गए विभिन्न प्रकार के अवकाश (असाधारण व अवैतनिक अवकाश छोड़कर) की गणना न होने से एसीपी का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

इसके किसी वर्ष में तीन माह से कम की अवधि के लिये वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि न दिये जाने की व्यवस्था में उस अवधि को भी एमएसीपी की गणना में नहीं लिया जा रहा था।

शासनादेश के मुताबिक, कर्मचारियों को अब यदि किसी वर्ष के दौरान तीन माह से कम अवधि के कार्यकाल के कारण किसी वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रवष्टि न लिखी गई हो तो एमएसीपी दिये जाने की तिथि से पहले के पाँच वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियों का संज्ञान लिया जाएगा। यदि उस अवधि में भी उत्तम एसीआर का मानक पूरा न हो रहा हो तो एमएसीपी की तिथि को आगे विस्तारित किया जाएगा।

उत्तराखंड में उत्कृष्ट सेवा के लिये 96 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान

चर्चा में क्यों ?

19 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा राज्य में बेहतर कार्य करने के लिये 96 पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा सम्मान दिये जायेंगे। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सूची जारी कर दी है।

प्रमुख बिंदु

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक पीटीसी नरेंद्रनगर दिनेश चंद्र बडोला व इंस्पेक्टर पूरण सिंह रावत को उत्कृष्ट सेवा पदक मिलेगा।

नोट :

इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक चंपावत जनपद के विपिन चंद्र पंत, निरीक्षक एसडीआरएफ हर्षवर्धन, निरीक्षक एसडीआरएफ हरक सिंह, एसआई दूरसंचार ख्याली दत्त जोशी, गजपाल सिंह रावत, अपर उप निरीक्षक मंगल सिंह, योगेंद्र सिंह व दिनेश चंद्र को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह व विशिष्ट कार्य के लिये प्रतिसार निरीक्षक जगदीश चंद्र पंत, निरीक्षक पुलिस दूरसंचार प्रमोद पेटवाल व एसआई विमलेश्वर प्रसाद रतूड़ी को उत्कृष्ट सेवा सम्मान से नवाज़ा जाएगा।

इसके साथ ही 14 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिये सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न व 70 पुलिस कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य के लिये सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न से सम्मानित किया जाएगा।

उत्तराखंड गृह विभाग में अब महिलाओं का दबदबा

चर्चा में क्यों ?

20 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड गृह विभाग में पाँच अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया, जिससे गृह विभाग के अहम पदों पर अब महिलाओं का दबदबा हो गया है।

प्रमुख बिंदु

गृह विभाग के अहम पदों पर अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी, विशेष गृह सचिव रिद्धिम अग्रवाल के बाद अब अपर सचिव के पद पर निवेदिता कुकरेती को तैनात किया गया है।

इसके अलावा आईटीडीए की ज़िम्मेदारी अब अमित सिन्हा से लेकर आई.ए.एस नितिका खंडेलवाल को सौंपी गई है। अमित सिन्हा निदेशक विजिलेंस के पद पर सेवाएँ देते रहेंगे।

वहीं शहरी विकास विभाग के अपर सचिव हरक सिंह रावत को स्टाफ ऑफिसर अध्यक्ष राजस्व परिषद की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई है। श्याम सिंह राणा को इस ज़िम्मेदारी से हटाकर अब केवल स्मार्ट सिटी एडिशनल सीईओ की ज़िम्मेदारी दी गई है।

एक अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे प्रदेश के 5500 सरकारी वाहन

चर्चा में क्यों ?

21 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में सरकारी विभागों, निगमों, निकायों, परिवहन निगम, विभाग, स्वायत्त संस्थाओं के 5500 वाहन 01 अप्रैल से कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा।

प्रमुख बिंदु

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि एक अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगी।

इसके दायरे में आने वाले वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने या किराए पर वाहन लेने के लिये सरकार को 300 से 550 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे।

संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि दिसंबर माह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप पॉलिसी के तहत मोटर यान अधिनियम में संशोधन का ड्राफ्ट जारी करते हुए सभी राज्यों से सुझाव मांगे थे।

उत्तराखंड ने जो सुझाव दिया था, उसमें बताया था कि 5500 वाहनों के कबाड़ में जाने के बजाय अगर उन्हें नीलाम किया जाए तो अपेक्षाकृत कम 11 करोड़ का नुकसान होगा। इसके अलावा दस लाख प्रति वाहन के हिसाब से देखें तो नए वाहन खरीदने को उत्तराखंड को 550 करोड़ की आवश्यकता होगी।

इसके बाद राज्य में 15 साल से पुराने किसी भी सरकारी वाहन का नवीनीकरण नहीं होगा, बल्कि उसे कबाड़ में देना होगा, जिसके लिये हर जिले में तीन कबाड़ केंद्र बनाए जा रहे हैं।

संयुक्त परिवहन आयुक्त ने बताया कि नई नीति के तहत एक अप्रैल से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का रिन्यूअल नहीं होगा। वह स्क्रैप में ही जाएंगे। 5500 वाहनों के कबाड़ बनने के बाद सभी विभागों को नए वाहन खरीदने होंगे। एक वाहन की औसत कीमत 10 लाख मानें तो राज्य को 550 करोड़ की जरूरत होगी।

सनत कुमार सिंह ने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल, 2023 से सभी तरह के भारी व्यावसायिक वाहनों को अनिवार्य तौर पर फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, जबकि प्राइवेट वाहनों के लिये यह व्यवस्था जून 2024 से लागू होगी।

नोट :

गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा उत्तराखंड का छोलिया नृत्य

चर्चा में क्यों ?

23 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी के.एस चौहान ने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड में अबकी बार उत्तराखंड की झाँकी के साथ कुमाऊँ का पारंपरिक छोलिया नृत्य की प्रस्तुति दिखेगी। इस बार राज्य की झाँकी मानसखंड पर तैयार की गई है।

प्रमुख बिंदु

राज्य के सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी के.एस चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड से 18 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे हैं।

झाँकी के अग्र व मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरन, बारहसिंघा, घुरल, मोर के अलावा राज्य में पाए जाने वाली विभिन्न पक्षियों, पृष्ठ भाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया जाएगा। प्रसिद्ध लोक कला 'ऐपण' का भी झाँकी के मॉडल में शामिल किया गया।

संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी के.एस चौहान ने बताया कि कर्तव्य पथ पर इस बार उत्तराखंड की झाँकी मानसखंड सबके लिये आकर्षण का केंद्र रहेगी। केदारनाथ व बदरीनाथ की तर्ज पर कुमाऊँ के पौराणिक मंदिरों के लिये मुख्यमंत्री के निर्देश पर मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना पर काम किया जा रहा है।

गणतंत्र दिवस परेड के माध्यम से देश-विदेश के लोग मानसखंड के साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति से भी परिचित होंगे। राज्य की झाँकी का निर्माण स्मार्ट ग्राफ आर्ट एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

एसएसपी दून और एसटीएफ को राज्यपाल पदक

चर्चा में क्यों ?

24 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में एसएसपी दून और एसएसपी एसटीएफ को राज्यपाल पदक दिये जाने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु

उल्लेखनीय है कि देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुँवर, एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल और एसपी चंपावत देवेंद्र पींचा को राज्यपाल पदक दिया जाएगा।

उन्हें यह पदक उत्कृष्ट सेवा के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

इनके अलावा सराहनीय कार्य के आधार पर उत्कृष्ट सेवा पदक के लिये भी तीन अधिकारियों का चयन हुआ है। इनमें अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा राकेश चंद देवी, अपर पुलिस अधीक्षक जीआरपी अरुणा भारती और अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस दूरसंचार पिथौरागढ़ बसंत बल्लभ तिवारी शामिल हैं।

उत्तराखंड में होमगार्ड और अग्निशमन सेवा के अधिकारियों व कर्मियों को राष्ट्रपति पदक

चर्चा में क्यों ?

26 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में होमगार्ड और अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

होमगार्ड के अधिकारियों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा गृह रक्षक पदक और सराहनीय सेवा गृह रक्षक पदक दिये गए हैं जबकि, अग्निशमन अधिकारियों को अग्निशमन सेवा पदक से नवाजा गया है।

नोट :

इन अधिकारियों को मिला पदक-

राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा गृह रक्षक पदक- अमिताभ श्रीवास्तव (डिप्टी कमांडेंट जनरल, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा), राजीव बलोनी (डिप्टी कमांडेंट जनरल, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)।

राष्ट्रपति सराहनीय सेवा गृह रक्षक पदक- गोविंद सिंह खाती (वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होमगार्ड जनपद (अल्मोड़ा), राजपाल राणा अवैतनिक प्लाटून कमांडर,(चमोली)।

विशिष्ट सेवा के लिये राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक- देवेंद्र सिंह, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (रूद्रप्रयाग), प्रताप सिंह राणा, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (हरिद्वार)।

दीर्घ एवं सराहनीय सेवा के लिये अग्निशमन सेवा पदक- श्याम सिंह, लीडिंग फायरमैन, (चंपावत), दिनेश चंद्र पाठक, लीडिंग फायरमैन (बागेश्वर), लक्ष्मण सिंह नेगी, लीडिंग फायरमैन (ऊधमसिंहनगर)।

वहीं एडीजी कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन को विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है। इनके अलावा सराहनीय सेवा के लिये पुलिस पदक पाने वालों में एएसपी मुख्यमंत्री सुरक्षा राकेश चंद्र देवली, पौड़ी गढ़वाल के डीएसपी श्यामदत्त नौटियाल, हरिद्वार के डीएसपी पंकज गैरोला, रुद्रपुर के हेड कांस्टेबल पीएसी अमीर चंद्र और दरोगा पुलिस मुख्यालय गिरवर सिंह रावत शामिल हैं।

सेना मेडल से सम्मानित होंगे उत्तराखंड के मेजर प्रशांत भट्ट

चर्चा में क्यों ?

25 जनवरी, 2023 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से की गई वीरता पुरस्कारों की घोषणा में उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले के कौसानी निवासी युवा सैन्य अधिकारी मेजर प्रशांत भट्ट को सेना मेडल के लिये चयनित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

उल्लेखनीय है कि युवा सैन्य अधिकारी मेजर प्रशांत भट्ट का सैनिक स्कूल से 12वीं पास करने के बाद प्रथम प्रयास में ही एनडीए में चयन हुआ था। वर्ष 2014 में वह भारतीय सेना की दो पैरा स्पेशल फोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर चुने गए। बाद में कमीशंड मिलने पर वह मेजर के पद पर पहुँचे।

सेवाकाल में बॉर्डर पर हुए कई सफल ऑपरेशन में उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता और साहस को देखते हुए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों के लिये चयनित जांबांजों में उन्हें भी सेना मेडल के लिये चुना गया है।

प्रशांत भट्ट को भारत सरकार ने कुशल नेतृत्व, कर्त्तव्य परायण, साहस और संवेदनशील मुद्दों को सरलता से हल करने पर सेना मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है।

ज्ञातव्य है कि मेजर प्रशांत भट्ट वर्तमान में मध्य प्रदेश के महू में जूनियर कमांड का प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं।

विदित है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सेना मेडल प्राप्त वीर जांबाज सैनिकों को पुरस्कार के तौर पर एकमुश्त 15 लाख रुपए और हर वर्ष 50,000 रुपए तथा भारत सरकार से भी लगभग इतनी ही धनराशि दी जाती है।

उत्तराखंड के खिलाड़ियों के 4% आरक्षण के अध्यादेश को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

27 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिये राज्य सरकार अध्यादेश ला रही है। न्याय विभाग ने अध्यादेश लाने को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश था, लेकिन 2013 में हाईकोर्ट ने इस शासनादेश को रद्द कर दिया था।

खेल मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जा सके, इसके लिये न्याय और कार्मिक विभाग से सहमति मिल गई है और इसके लिये नियमावली बनाई गई है।

नोट :

कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लाकर या विधानसभा के माध्यम से इसे कानून बनाया जाएगा। इससे प्रदेश में खेल का और बेहतर माहौल बनेगा व खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा।

खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि प्रदेश सरकार हरियाणा राज्य की तर्ज़ पर उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को 5400 ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देने की तैयारी कर रही है। इसके लिये तैयार प्रस्ताव को वित्त और कार्मिक विभाग से मंज़ूरी मिल गई है।

इसका शासनादेश जारी होते ही हरियाणा के बाद उत्तराखंड पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।

खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उत्तराखंड को खेलभूमि के नाम से भी जाना जा सकेगा।

उत्तराखंड सरकार अगले दो साल में बनवाएगी 50 हज़ार पॉली हाउस

चर्चा में क्यों ?

29 जनवरी, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की अगले दो साल में उत्तराखंड में 50 हज़ार पॉली हाउस बनाने की योजना है।

प्रमुख बिंदु

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सरकारी आवास में पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उन्होंने किसानों के लिये सरकार की पॉली हाउस बनाने की योजना के बारे में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की मदद से इन पॉली हाउसों का निर्माण करेगी।

मुख्यमंत्री ने योजना पर विश्वास जताते हुए कहा कि पॉली हाउस बनने से उत्तराखंड के किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा।

गौरतलब है कि पॉली हाउस एक प्रकार का ग्रीनहाउस है, जहाँ विशेष प्रकार की पॉलीथिन शीट का उपयोग कवरिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसके तहत फसलों को आंशिक रूप या पूरी तरह से नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में उगाया जा सकता है।

दूसरे शब्दों में, वर्तमान समय में आधुनिक ढंग से कृषि करने, अर्थात् फसलों को उगाने के लिये एक विशेष प्रकार की पालीथिन या चादर से ढका हुआ घर होता है। इस घर के वातावरण को फसलों के अनुकूल कर हर मौसम में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। पॉली हाउस में बाहरी वातावरण का प्रभाव नही पड़ता है। पॉली हाउस को शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस और नेट हाउस आदि नामों से जाना जाता है।

दरअसल पॉली हाउस खेती खेती का एक आधुनिक तरीका है, जिसमें हम हानिकारक कीटनाशकों और अन्य रसायनों के अधिक उपयोग के बिना उच्च पोषक मूल्यों के साथ अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लागू होगा समान शैक्षिक कैलेंडर

चर्चा में क्यों ?

30 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सचिवालय में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में बेहतर शैक्षिक वातावरण के लिये सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि समान शैक्षणिक कैलेंडर के तहत विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में छात्रों के लिये एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव एवं एक दीक्षांत समारोह की थीम पर कार्य करते हुए एकरूपता लाई जाएगी।

समीक्षा बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य में समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक शैक्षणिक वातावरण के लिये सभी विश्वविद्यालय में प्रवेश की तिथि, परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम, छात्रसंघ चुनाव व दीक्षांत समारोह के लिये समान एकेडमिक कैलेंडर लागू किया जाएगा।

इसके लिये सभी विश्वविद्यालय के कुलपति आपस में बैठकर दो सप्ताह में शैक्षणिक कैलेंडर का ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जिसको अगली बैठक में अंतिम रूप देते हुए स्वीकृति के लिये शासन को भेजा जाएगा।

नोट :

विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा के आयोजन का कार्य महीनों चलता रहा है, जिससे परीक्षाएँ समय पर नहीं हो पाती हैं। इससे परिणाम घोषित करने में भी देरी होती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को अपने संबद्ध महाविद्यालयों में 180 दिवस अनिवार्य रूप से कक्षाएँ संचालित करनी होगी। साथ ही छात्र-छात्राओं को पुस्तकालयों में बैठकर अध्ययन करने के लिये प्रेरित करना होगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा में बैठने के लिये छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा को गुणवत्ता एवं रोज़गारपरक बनाने के लिये विश्वविद्यालय एवं सभी कॉलेजों को नैक मूल्यांकन कराना ज़रूरी है।

सभी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह की समान वेश-भूषा व दीक्षा शपथ एकसमान होगी। एक जैसी दीक्षा शपथ के लिये संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. देवेंद्र शास्त्री की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जो दीक्षा शपथ का ड्राफ्ट एवं वेश-भूषा तय कर शासन को उपलब्ध कराएगी।

बैठक में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली ने कहा कि नए शैक्षिक सत्र से सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश समर्थ पोर्टल से अनिवार्य रूप से किये जाएंगे। एकेडमिक गतिविधियों के साथ ही शोध कार्यों एवं कौशल विकास संबंधी पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जाएगी।

गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झाँकी को मिला प्रथम स्थान

चर्चा में क्यों ?

30 जनवरी, 2023 को केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की परेड (Republic Day Parade 2023) में शामिल राज्यों की झाँकियों के पुरस्कार का ऐलान किया, जिसमें उत्तराखंड की झाँकी मानसखंड को देशभर में प्रथम स्थान मिला।

प्रमुख बिंदु

गणतंत्र दिवस की परेड में कर्त्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गई सभी झाँकियों में उत्तराखंड की झाँकी को प्रथम पुरस्कार मिला। उत्तराखंड ने राज्य के वन्यजीवों और धार्मिक स्थलों की थीम पर झाँकी प्रदर्शित की थी।

उत्तराखंड की झाँकी में उत्तराखंड का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क, बारहसिंगा, उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग, गोरल, देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर, उत्तराखंड के प्रसिद्ध पक्षी घुघुती, तीतर, चकोर, मोनाल के साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध ऐपण कला को प्रदर्शित किया गया था।

झाँकी में प्रसिद्ध पौराणिक जागेश्वर धाम मंदिर को दिखाया गया था। मंदिर के आगे और पीछे घनघोर देवदार के वृक्षों का सीन तैयार किया गया था। झाँकी के आगे और पीछे उत्तराखंड का नाम भी ऐपण कला से लिखा गया था।

गढ़वाल की चारधाम यात्रा की भाँति सरकार कुमाऊँ में मंदिर माला मिशन के अंतर्गत पर्यटन बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसी के दृष्टिगत प्रसिद्ध पौराणिक जागेश्वर धाम को दिखाया गया था।

टीम लीडर और संयुक्त निदेशक सूचना के.एस. चौहान के नेतृत्व में झाँकी में उत्तराखंड की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिये छोलिया नृत्य करने में पिथौरागढ़ के भीम राम के दल के 16 कलाकारों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। इसी के साथ झाँकी के ऊपर बारु सिंह और अनिल सिंह ने योग करते हुए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गणतंत्र दिवस की परेड में 23 झांकियाँ प्रदर्शित की गईं। इनमें से 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और 6 झांकियाँ मंत्रालयों और विभागों से थीं।

विदित है कि सितंबर माह में भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों एवं मंत्रालयों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं। अक्टूबर तक राज्य सरकारें विषय का चयन कर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजती हैं। उसके बाद भारत सरकार प्रस्तुतीकरण के लिये आमंत्रित करती हैं।

पहली बार की मीटिंग में विषय के आधार चार्ट पेपर में डिजाइन तैयार कर प्रस्तुत करना होता है। आवश्यक संशोधन करते हुए तीन बैठकें डिजाइन निर्माण के संदर्भ में होती हैं। जिन प्रदेशों के डिजाइन कमेटी को सही नहीं लगते हैं उनको शार्टलिस्ट कर देती हैं। उसके बाद झाँकी का मॉडल बनाया जाता है। थीम सांग 50 सेकेंड का होता है, जो उस प्रदेश की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, जब सभी स्तर से भारत सरकार की विशेषज्ञ समिति संतुष्ट हो जाती हैं, तब झाँकी का अंतिम चयन किया जाता है।

नोट :